सत्यमेव जयते
Government of India

NCGG
National Centre for Good Governance
The Torch Bearer of Good Governance

वार्षिक रिपोर्ट | 2018-19

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का स्वायत्त संस्थान

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी)

मुख्यालय

चौथा तल, ब्लॉक- IV, पुराना जेएनयू परिसर, न्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली-110067

टेलीफोन 011-26169139, 011-26169137, 011-26169136

शाखा कार्यालय

कोज़ी नुक कॉम्प्लेक्स, चार्लीविले रोड़, मसूरी, उत्तराखंड-248179

टेलीफोन + 91-135-2632485, +135-2632663, +91-2632663, 2630917

2018-19

वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान

विषय वस्तु

केंद्र के बारे में	2
वर्ष 2018-19 के दौरान एनसीजीजी के कार्यकलाप	4
एनसीजीजी, मसूरी में उपलब्ध सुविधाएं	8
एनसीजीजी टीम	9
संलग्नक-I राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के शासी निकाय के सदस्यगण	12
संलग्नक- II राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की प्रबंधन समिति के सदस्यगण	13
संलग्नक-III 'नागरिक केंद्रिक शासन : प्रपत्रों का सरलीकरण'	14
संलग्नक-IV अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
संलग्नक-V राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	18
संलग्नक-VI प्रबंधन विकास कार्यक्रम	18
संलग्नक-VII राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र के कार्यकलाप : जल और स्वच्छता	19

NCGG

परिचय

I. केंद्र के बारे में:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और शाखा कार्यालय मसूरी में स्थित है।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) की स्थापना अध्ययनों, प्रशिक्षण, ज्ञान की साझेदारी और उत्तम विचारों के प्रोत्साहन के जरिए शासन में सुधार लाने हेतु सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। इससे नीति संगत शोध कार्य करने एवं मामला अध्ययन तैयार करने, भारत और अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों के लिए सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने, मौजूदा ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु मंच उपलब्ध कराने औरराष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय रुप से ज्ञान प्राप्त करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए विचार विकसित करने की अपेक्षा की जाती है।

II. एनसीजीजी का अधिदेश:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की देश के शीर्ष थिंक-टैंक के रूप में परिकल्पना की गई है जो सरकार का मार्गदर्शन और सुशासन सुधारों को लागू करने में सरकार की सहायता करेगा। इससे राष्ट्रीय से प्रादेशिक और स्थानीय स्तर तथा सरकार के सभी सेक्टरों से संबंधित शासन के समस्त मुद्दों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उच्चस्तरीय संस्थान बनने की अपेक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य भारत भर में अपने क्षेत्राधिकार के साथ राष्ट्रीय स्तर का बहुविषयक संस्थान बनने का है जो सुशासन कार्यनीति, कार्रवाई योजना और उनके कार्यान्वयन में सहायता के लिए सक्रिय शोध और विश्लेषणात्मक अध्ययन के प्रति समर्पित हो।

केंद्र के कार्य का परिणाम शोध-पत्रों, शासन-सुधारों पर श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन और नीति विश्लेषण के रूप में है। इसका लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को आवश्यक निदेश, मार्गदर्शन और शासन में क्षमता-निर्माण के इनपुट उपलब्ध कराना है।

III. उद्देश्य:

एनसीजीजी के उद्देश्य और कार्य इस प्रकार हैं :

i. प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के मध्य एवं शासन एवं नीतिगत सुधारों के लिए विचार-मंडल होना,

ii. श्रेष्ठ प्रथाएं,पहल और कार्यप्रणालियां जो सुशासन, ई-गवर्नेंस, नवाचार, और सरकार के भीतर परिवर्तन-प्रबंधनको प्रोत्साहित करें, के राष्ट्रीय सूचना कोष के रूप में कार्य करना।

iii. राष्ट्रीय/राज्य और स्थानीय स्तर पर विनियामक और विकासात्मक प्रशासन,लोक नीति,शासन और लोक प्रबंधन के विविध पहलुओं पर सक्रिय शोध तथा क्षमता निर्माण शुरू करना और उनमें सहभागिता करना।

iv. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागोंतथा राज्य सरकारों के बीच सहक्रियाशीलता विकसित करना और शासन में प्रमुख मुद्दों पर परामर्श देना

v. शासन में नवाचारी विचारों और श्रेष्ठ प्रथाओं की साझेदारी और रेप्लिकेशन तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में क्षमता- निर्माण को प्रोत्साहन देना।

vi. देश के भीतर और बाहर परामर्श सेवा कार्य करना

vii. सरकार के भीतर और बाहर शोधरत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ पारस्परिक संवाद।

IV. शासी निकाय:

एनसीजीजी मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय द्वारा शासित है। सोसायटी के कार्य शासी निकाय की देखरेख, निदेश और नियंत्रण से प्रबंधित किए जा रहे हैं। शासी निकाय के सदस्यों की सूची **संलग्नक-I** पर दी गई है।

V. प्रबंधन समिति:

एनसीजीजी की एक प्रबंधन समिति है जिसके अध्यक्ष कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव हैं। प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची **संलग्नक-II** पर दी गई है।

NCGG

वर्ष 2018-19 के दौरान एनसीजीजी के कार्यकलाप

I. नागरिक केंद्रिक शासन' प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) देश में सुशासन सुधारों को लागू करने के लिए मंच की सुविधा उपलब्ध करवाता रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इसके पास विज़न और माननीय प्रधानमंत्री का शासनादेश भी है। एनसीजीजी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से प्रपत्रों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए पहलों की श्रृंखला शुरु की है।

कार्यशाला के उद्देश्य हैं :

1. उपयोगकर्ताओं के नज़रिये से प्रपत्रों की समीक्षा में हित-धारकों को जोड़ना।
2. प्रपत्रों में सूचना के प्रवाह और प्रक्रिया के बंधन को सरल बनाने में अपेक्षित बदलावों पर विचार-विमर्श किया गया।
3. प्रपत्र में अपेक्षित बदलाव को समझना और संबंधित प्राधिकारियों को बदलाव के लिए सुझाव देना।
4. अप्रचलित प्रपत्रों को हटाना।

कार्य- प्रणाली

अब तक अपनाई गई कार्यप्रणाली में चार चरण हैं: विभागीय कर्मचारियों के कोर ग्रुप का गठन; कोर ग्रुप के साथ एक सप्ताह या उससे आगे तक सघनता से काम करना; सुझाए गए बदलावों और विभाग द्वारा प्रस्तावित बदलाव अपनाए जाने पर चर्चा के लिए हित-धारकों के साथ-साथ संबंधित विभागीय कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक या एकाधिक तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन।

अंतिम कार्यशाला के बाद एनसीजीजी और संबंधित विभागीय अधिकारी सुझाए गए सरलीकृत प्रपत्रों पर कार्य करते हैं। विभाग सरलीकृत प्रपत्रों को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया करता है।

वर्ष के दौरान एनसीजीजी ने**18** मई, **2018** को सिविल सेवा अधिकारी संस्थान (सीएसओआई), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में **संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार** के लिए नागरिक केंद्रिक शासन – प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया।

एनसीजीजी ने' नागरिक केंद्रिक शासन' प्रपत्रों का सरलीकरण पर **कुल 24 कार्यशालाएं आयोजित किए हैं।** वर्ष 2015-18 के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की सूची **संलग्नक- III** में दी गई है।

II. भारत के लिए गैर-नेटवर्क स्वच्छता प्रणाली पर राष्ट्रीय कार्यशाला

एनसीजीजी ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से 27-28 फरवरी,2019 को मसूरी में दो दिवसीय **'राष्ट्रीय कार्यशाला: भारत के लिए गैर-नेटवर्क स्वच्छता प्रणाली'** का आयोजन किया।

II. लोक नीति और शासन पर अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. बंगलादेश के सिविल सेवक

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र अप्रैल, 2013 से एनसीजीजी, मसूरी में बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता रहा है। विदेश मंत्रालय ने एनसीजीजी को बंगलादेश के 1500 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने का अधिदेश दिया है।

बंगलादेश के 1500 सिविल सेवकों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण सम्पन्न करने बाद, **अगले 6 (छह) वर्ष में**

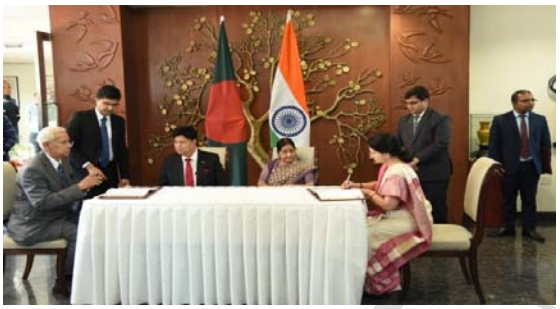

1800 बंगलादेशी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण करने के लिए राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) और लोक प्रशासन मंत्रालय,बंग्लादेश सरकार के मध्य 11 फरवरी,2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह सहयोग भारत और बंगलादेश के बीच प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है।इस तरह के प्रशिक्षण दोनों देशों के सिविल सेवकों के मध्य प्रशासन के अनुभवों को साझा करने और मजबूत द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने में सहायता का अवसर प्रदान करते हैं।अब सिविल सेवाओं का बल प्रशासन के बजाय विकास कार्यकलापों की ओर अंतरित हो गया है, इसीलिए भारत एवं बंगलादेश के सिविल सेवक एक दूसरे को समझते हुए दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रगाढ़ संबंधों को प्रोत्साहित करने में सहायता करेंगे।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बंगलादेश के दौरे के दौरान बंगलादेश और भारत के मध्य 7 जून, 2015 के संयुक्त घोषणा पत्र के दौरान सीबीटीपी कार्यक्रमों के महत्व तथा बंगलादेश के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। बंगलादेश के प्रधानमंत्री ने

8 अप्रैल, 2017 को भारत दौरे के दौरान क्षमता निर्णाण प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर संतोष व्यक्त किया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रकार है:

- भारतीय प्रशासनिक और शासन प्रणालियों से अवगत होना।
- भारतीय ग्रामीण विकास पद्धतियों और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों की गहन समझ प्राप्त करना।
- शहरी विकास योजना की गहन समझ प्राप्त करना और अपनाई गई श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों से सीख प्राप्त करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में भारत की विविध उत्तम ई-गवर्नेंस अनुभवों से अवगत होना।
- मामला अध्ययनों के जरिए आपदा प्रबंधन तकनीकों और पद्धतियों से सीख प्राप्त करना।
- उत्तम परियोजनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करना।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची **संलग्नक-IV** में दी गई है।

ख. म्यांमार के नगर प्रशासक

एनसीजीजी ने **25 मार्च से 06 अप्रैल,2019 तक म्यांमार के जिला और नगर प्रशासकों के लिएपहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया** जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- स्थायी विकास के लिए सुशासन और लोक नीति की भूमिका का विशेष रूप सेउल्लेख करते हुए नीतिगत संवाद और ज्ञान की साझेदारी के लिए मंच उपलब्ध कराना।

- क्षेत्र में शासन, फील्ड प्रशासन और लोक नीति से संबंधित सीख,एक-दूसरे देशों के अनुभव और श्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों की साझेदारी को सुविधाजनक बनाना।
- सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आईटी अनुप्रयोगों और ई-सरकार सहित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपनाए गए कार्यढ़ाचों की विस्तृत पूर्ण जानकारी।

- लोक नीति और शासन के अंतर- विषयक क्षेत्र मुख्यतः शिक्षा,स्वास्थ्य,शहरी सुधार,वित्तीय नीति,ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य अनेक क्षेत्रों की विस्तृत पूर्ण जानकारी।
- ढ़ाचागत विकास/ वियुत परियोजनाओं/ परिवहन आदि जैसे अनेक क्षेत्रों की अच्छी परियोजनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव।

प्रशिक्षण इनपुट्स में शासन-सिंहावलोकन,प्रशासन में नैतिकता,पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, नेतृत्व मॉड्यूल,भारत में शिक्षा परिदृश्य-नीति और प्रथा, ग्रामीण विकास की डिजिटल इंडिया शासन चुनौतियां,आधार-सुशासन का साधन, स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार, नीति निर्णयन- मामला अध्ययन और अभ्यास, ऊर्जा सुधार, भारत में कृषि क्षेत्र, पर्यावरण और लोक नीति, पीपीपी का सिंहावलोकन,लोक सेवा प्रदायगी अधिनियम, आपदा प्रबंधन-भारत की श्रेष्ठ प्रथाएं और पद्धतियां, निर्वाचन सुधार आदि विषयों को सम्मिलित करते हुए मॉड्यूलर पद्धति अपनाई जाती है।

III. लोक नीति और शासन पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों जैसेकि असम, ओडिशा और मध्य प्रदेश के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनसीजीजी नेराज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों जैसेकि असम, ओडिशा और मध्य प्रदेश के लिए लोक नीति और शासन पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमआयोजित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची *संलग्नक V* में दी गई है।

ख. प्रबंधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :

एनसीजीजी ने वर्ष के दौरान मसूरी में कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा लोक सभा सचिवालय एवं राज्य सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पांच-दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रमसफलतापूर्वक आयोजित किए।
वर्ष **2018-19** के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की सूची *संलग्नक VI* में दी गई है।

ख. जल तथा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के लिए राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र :

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, मसूरी को जल और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में अपने पैनल में रखा है। एनसीजीजी के राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र (एनकेआरसी) का उद्देश्य वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों तथा इस क्षेत्र में काम कर रहे प्रमुख नीति-निर्माताओं को नवीनतम विकास से अवगत कराना तथा उन्हें उस जानकारी से सज्जित करना है जो उन्हें क्षेत्रक की व्यापक समझ विकसित करने और उन्हें अधिक प्रभावी हस्तक्षेप करने योग्य बनने में सहायता करेगी।

घ. जल तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करता रहा है जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार

द्वारा जल एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) दोनों अलग-अलग क्षेत्रकों में सौंपी गई है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम जल एवं स्वच्छता क्षेत्रक में संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। हालांकि, 2012 के बाद जल एवं स्वच्छता (अब स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण) के लिए प्रशिक्षण पृथक रूप से संचालित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में हस्तक्षेपों के लिए लक्ष्य-समूह विकास एजेंसियों के प्रशासक, पीएचईडी के इंजीनियर, पीआरआई और विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और इसके उद्देश्य:

विश्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयास बढ़ाने और स्वच्छता पर फोकस करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने का है। इस अभियान का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्ति से साफ-स्वच्छ बनाते हुए उपयुक्त ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण भारत के साफ-सफाई का स्तर सुधारने का है।

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के मुख्य उद्देश्य:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना;

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्राम पंचायतें 2019 तक निर्मल-स्थिति प्राप्त कर लें, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज बढ़ाना;

(iii) जागरुकता-सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सतत स्वच्छता सुविधाओं का संवर्धन करते हुए पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों को प्रेरित करना;

(iv) सतत स्वच्छता के लिए पारिस्थितिकीय व आर्थिक दृष्टि से प्रभावी प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; तथा

(v) ग्रामीण क्षेत्रों की समूची सफाई पर फोकस करते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणाली विकसित करना।

ङ. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर डीएम/डीसी/सीईओ/ जिला परिषद अध्यक्षों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम:

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस), भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र को जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने का कार्य सौंपा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरुकता उत्पन्न करना, ज्ञान अर्जित करना और श्रेष्ठ प्रयोग सीखना तथा देशभर में राष्ट्रीय अभियान की सततता और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर डीसी/डीएम/सीईओ/जिला परिषद के अध्यक्षों, बीडीओ के लिए एनसीजीजी द्वारा उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखलाएं आयोजित की गई थीं।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की सूची **संलग्नक-VII** में दी गई है।

एनसीजीजी, मसूरी में उपलब्ध सुविधाएं

भवन परिसर में संकाय कक्ष, स्टॉफ के लिए कार्यालय स्थल, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, अतिथि कक्ष, भोजन कक्ष, रसोईघर और प्रतीक्षालय है।

पुस्तकालय में क्षेत्रीय और शहरी आयोजना पर विशेष संग्रह, पर्यावरणीय अध्ययन और एनसीजीजी द्वारा किए गए विभिन्न शोध-पत्रों की रिपोर्टें उपलब्ध हैं। कंप्यूटरीकृत सूचीपत्र तथा अकादमी की गांधी स्मृति पुस्तकालय की ग्रंथ-सूची सेवाएं भी केंद्र के उपयोग हेतु उपलब्ध है।

कंप्यूटर प्रयोगशाला में दस कार्य स्टेशन हैं, डिजीटलीकरण और स्कैन करने की सुविधाएं, रंगीन प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग और सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

सम्मेलन कक्ष में 40 प्रतिभागीगण बैठ सकते हैं तथा इसमें मल्टीमीडिया सुविधाएं भी हैं।

NCGG

एनसीजीजी टीम

एनसीजीजी के पदाधिकारीगण और संकाय सदस्य

श्री के.वी. इपेन, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा महानिदेशक, एनसीजीजी (दिसम्बर, 2017 से आज की तारीख तक) : वे असम मेघालय संवर्ग के 1984 बैच के भा.प्र.सेवा के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र तथा सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग हैं। वह पूर्व में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।अपने कैरियर में अपर मुख्य सचिव/अपर सचिव, जन जातीय कार्य मंत्रालय, श्रम विभाग, आयोजना और विकास विभाग, अध्यक्ष, विद्युत विभाग जैसे अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वाशिंगटन में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी जिसमें वह बंगलादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के मामलों का कार्य देखते रहे। वह अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं तथा यूनाइटेड किंगटम से मेक्रो इकॉनामिक पॉलिसी एंड प्लानिंग में भी स्नातकोत्तर हैं तथा प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा धारक हैं। उन्होंने डब्ल्यूटीओ, अवसंरचना विकास और वित्तपोषण तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहित अनेक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।

Jhefr **पूनम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर :** राजनीतिशास्त्र में स्नातकोत्तर, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा उत्तराखंड, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी। वह सामाजिक क्षेत्र विशेषकर आयोजना, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्र की विशेषज्ञा हैं। वह मुख्यालय, एनसीजीजी, नई दिल्ली में प्रशिक्षण नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने गया कॉलेज, गया (मगध विश्वविद्यालय, बिहार) में 1990-94 तक लेक्चरर के रूप में कार्य किया है तथा वर्ष, 1998 से सितम्बर, 2005 तक बिहार शिक्षा परियोजना, डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान में कार्य किया है। वह पूर्ववर्ती एनआईएआर (अब एनसीजीजी) में अक्तूबर, 2005 से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं तथा गवर्नेंस मामलों से संबंधित शोध, मॉनीटरिंग और प्रशिक्षण की विभिन्न परियोजनाओं का समन्वयन कर रही हैं। उनके प्रकाशन समुदाय शासन और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। उन्होंने समुदाय शासन पर 20 मामला अध्ययन कार्य और 12 श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर कार्य किए हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार के 15 विभागों/ मंत्रालयों के लिए 'नागरिक केंद्रिक शासन' प्रपत्रों का सरलीकरण पर 24 राष्ट्रीय कार्यशालाओं का समन्वयन किया है।

डॉ. ए.पी. सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर : सांख्यिकीय में एम.फिल और पीएचडी। उन्हें सामाजिक विज्ञान शोध करने तथा प्रबंधन, शासन, प्रशासन और सरकारी निजी भागीदारी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजन करने का लम्बा अनुभव है। वह सांख्यिकीय और सामाजिक विज्ञान शोध जैसे भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं तथा उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के अनेक शोध अध्ययन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर प्रकाशित किए हैं। उन्होंने विभिन्न देशों के सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसेकि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवक, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक समन्वयन किया है।

डॉ. भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, एसोसिएट प्रोफेसर : कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखंड) से भूगोल विज्ञान में एम.ए, पीएचडी। उन्हें अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण में 20 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने जीबीपीआईएचईडी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन) में अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया तथा उन्होंने उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में भी संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके 30 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित हो चुके हैं तथा उन्होंने दो पुस्तकों "सैनिटेशन एंड हेल्थ इन रूरल इंडिया : प्राब्लम एंड मैनेजमेंट आप्शन्स" का श्री आलोक कुमार, भा.प्र. सेवा, पूर्ववर्ती उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा "डिसेन्ट्रालाइज्ड गवर्नेंस ऑन वाटर एंड सैनिटेशन इन इंडिया" का श्री कुश वर्मा, भा.प्र. सेवा पूर्ववर्ती, महानिदेशक, एनसीजीजी और डॉ एडेन क्रोनिन, चीफ वाटर एंड सैनिटेशन, यूनिसेफ, इंडोनेशिया के साथ संपादन कार्य किया। डॉ बिष्ट ने देश भर में जल और स्वच्छता, लोक नीति एवं शासन पर 90 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दूरदर्शी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित किए। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों और विदेश में अनेक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।

डॉ गजाला हसन, एसोसिएट प्रोफेसर : जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.कॉम, पीएचडी (वाणिज्य) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल्स (डीटीएस) पाठ्यक्रम। वह सामाजिक क्षेत्र के विविध शोध अध्ययनों, एसएसए, प्रशिक्षण और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में शामिल रही हैं।

श्री संजीव शर्मा, रिसर्च एसोसिएट : एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से एम.ए. (समाज विज्ञान), एम.ए. (अंग्रेजी), साईनाथ विश्वविद्यालय, रांची से पीएचडी (समाज विज्ञान) कर रहे हैं, एमसीआरपी विश्वविद्यालय, भोपाल से पीजीडीसीए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस)। उन्होंने ग्राफिक्स एरा, देहरादून से डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स तथा ऑटो कैड (सीएडी) भी किया है। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और पुस्तकों में अनुसंधान लेख प्रकाशित किए हैं तथा वह भिन्न-भिन्न सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न शोध अध्ययनों के समापन और प्रकाशन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं। वह एसपीएसएस आदि जैसे पैकेजों के उपयोग से मात्रात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण सहित स्किल्स प्राप्त हैं।वह सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवकों, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं।

डॉ मुकेश के. भंडारी, रिसर्च एसोसिएट : एम.ए. (राजनीति शास्त्र), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, पीएचडी (राजनीतिशास्त्र) एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, बम्बई से स्थानीय स्व-शासन में डिप्लोमा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस) कोर्स। उन्होंने "इंडीजनस पीपुल राइटस" पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्य के जिला अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रज्ञा अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने उत्तराखंड राज्य में लोकनीति : सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली द्वारा आयोजित अनुसंधान कार्यक्रम : विधानसभा चुनाव अध्ययन, 2002 (चुनाव पश्चात् – सर्वेक्षण) में फील्ड सर्वेक्षक का कार्य किया। वह सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवकों, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन में सफलतापूर्वक

जुड़े रहे हैं।

श्री संदीप गर्ग, वित्त अधिकारी : बी.एस.सी. भौतिकी (आनर्स)। वह वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग में अधिकारी हैं। उन्होंने आईएनजीएएफ द्वारा आयोजित कंप्यूटर लेखापरीक्षा तकनीकों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्हें पीएफएमएस ऑनलाइन पोर्टल तथा सरकारी लेखा और आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य-अनुभव है।

केआरसी परियोजना :

डॉ. ए.के. मिश्रा, परियोजना परामर्शदाता (जल और स्वच्छता परियोजना), केआरसी : एम.एससी (रसायन विज्ञान), बी.ईडी, कुमायूँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, नैनीताल, एम.ए. (समाज विज्ञान), पीएचडी (समाज विज्ञान) गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर। उन्हें अनुसंधान, सामाजिक संसाधन जुटाने, प्रशिक्षण, आयोजना, निष्पादन, मॉनीटरिंग तथा समुदाय प्रेरित, मांग प्रतिक्रियाशील पद्धति आधारित परियोजनाओं के समग्र प्रबंधन का 12 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में विशेषज्ञ (जल और स्वच्छता) के रूप में कार्य किया है। उन्होंने वर्ष 2007-08 के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्य हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) के सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों तथा विदेश विशेषकर कनाडा, नेपाल और थाइलैंड में अनेक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।

NCGG

संलग्नक-I

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के शासी निकाय के सदस्यगण

1.	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
4.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
7.	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
9.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
10.	सचिव, कृषि,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	सदस्य
11.	शिक्षाविद / प्रख्यात प्रशासक / विशेषज्ञ / प्रतिष्ठित नवप्रवर्तक / प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख	सदस्य **(5)**
12.	महानिदेशक, एनसीजीजी	सदस्य सचिव

संलग्नक- II

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की प्रबंधन समिति के सदस्यगण

1.	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सचिव समन्वय, मंत्रिमंडल सचिवालय	सदस्य (पदेन)
3.	एसएस/एएस एवंएफए (गृह)	सदस्य (पदेन)

सचिवगण अथवा उनके नामिती जो संयुक्त सचिव स्तर से कम नहीं हों

4.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य (पदेन)
10.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य (पदेन)
11.	कृषि,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
12.	महानिदेशक, एनसीजीजी	सदस्यसचिव

संलग्नक-III

'नागरिक केंद्रिक शासन: प्रपत्रों का सरलीकरण'

क्र. सं.	कार्यशाला का नाम	स्थान	तारीख
1.	"नागरिक केंद्रिक शासन" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला - भाग- I औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	12-09-2015
2.	"नागरिक केंद्रिक शासन" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला - भाग- II कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) महानिदेशक श्रम कल्याण (डीजीएलडब्ल्यू) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)	विज्ञान भवन सौध,नई दिल्ली	18-12-2015
3.	नागरिक-केन्द्रिक शासन: प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला (डीओपीटी)	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	29-06-2016
4.	"नागरिक केंद्रिक शासन" प्रपत्रों का सरलीकरणपर तकनीकी कार्यशाला -श्रम कल्याण महानिदेशालय	सेमिनार कक्ष नंबर 1 और 2 (सम्मिलित), नई दिल्ली	29-09-2016
5.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण, पर तकनीकी कार्यशाला, भाग- I दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (दिव्यांगजन)	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्सी), सम्मेलन कक्ष -II, नई दिल्ली	15-11-2016
6.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, भाग- II दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (दिव्यांगजन)	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, सम्मेलन कक्ष -1, नई दिल्ली	22-11-2016
7.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, सम्मेलन कक्ष -1, नई दिल्ली	25-11-2016
8.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्सी), सम्मेलन कक्ष -II, बेसमेंट,नई दिल्ली	29-11-2016
9.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला,भाग- I नागरविमानन विभाग	सम्मेलन कक्ष - II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	21-12-2016
10.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	12-01-2017

	सरलीकरणपर तकनीकी कार्यशाला, भाग-II नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय	(एनेक्सी), व्याख्यानकक्ष -1, नई दिल्ली	
11.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्सी), व्याख्यानकक्ष -1, नई दिल्ली	08-02-2017
12.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	व्याख्यान कक्ष - II (बेसमेंट), इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्सी), 40, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली	02-03-2017
13.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, डाक विभाग, संचार मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष - II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	29-03-2017
14.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, भाग - II डाक विभाग, संचार मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष - II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	24-04-2017
15.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरणपर तकनीकी कार्यशाला, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	व्याख्यान कक्ष - II (बेसमेंट), इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्सी), 40, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली	27-04-2017
16.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, महिला एवं बाल विकास विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष - II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	31-05-2017
17.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरणपर तकनीकी कार्यशाला, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याणविभाग; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	हॉल -1 सिविल सेवा अधिकारी संस्थान	30-06-2017
18.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याणविभाग; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष - II, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	31-07-2017

19.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, आयुक्त (हथकरघा) कपड़ा मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष - **II**, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	**30-08-2017**
20.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरणपर तकनीकी कार्यशाला, आयुक्त (हथकरघा) कपड़ा मंत्रालय	सम्मेलन कक्ष - **II**, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	**06-10-2017**
21.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरणपर तकनीकी कार्यशाला, डाक विभाग, संचार मंत्रालय	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, सम्मेलन कक्ष - **I**, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली	**30-11-2017**
22.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, सम्मेलन कक्ष - **I**, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली	**23-02-2018**
23.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरण पर तकनीकी कार्यशाला, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, सम्मेलन कक्ष - **I**, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली	**28-03-2018**
24.	"नागरिक केंद्रिक शासन " प्रपत्रों का सरलीकरणपर तकनीकी कार्यशाला, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार	सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, सम्मेलन कक्ष - **I**, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली	**18-05-2018**

संलग्नक-IV

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 44वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 जुलाई, 2018 से 11 अगस्त, 2018	मसूरी और दिल्ली
2.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 45वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27 अगस्त, 2018 से 8 सितंबर, 2018	मसूरी और दिल्ली
3.	बंगलादेश के उपायुक्तों के लिए 8वां विशेष प्रशिक्षण	29 अगस्त, 2018 से 7 सितंबर, 2018	मसूरी और दिल्ली
4.	बंगलादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 46वां मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25 फरवरी, 2019 से 9 मार्च, 2019	मसूरी और दिल्ली
5.	म्यांमार के जिला प्रशासकों के लिए पहला मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25 मार्च, 2019 से 6 अप्रैल, 2019	मसूरी और दिल्ली

संलग्नक-V

राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1.	केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	23 मई, 2018 से 1 जून, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
2.	मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर कार्यक्रम प्रशिक्षण	21-25 मई, 2018	एनसीजीजी,मसूरी
3.	ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर 7वां प्रशिक्षण कार्यक्रम	22-26 अक्तूबर, 2018	एनसीजीजी,मसूरी
4.	"असम के विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों के लिए व्यावसायिक परिदृश्य विकसित करने में कार्यनीतिक विशेषताओं का विकास" पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "	22 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
5.	ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर 8वां प्रशिक्षण कार्यक्रम	28 जनवरी, 2019 से 1 फरवरी, 2019	एनसीजीजी, मसूरी
6.	असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिविल इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	4-16 मार्च, 2019	एनसीजीजी, मसूरी

संलग्नक-VI

प्रबंधन विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1.	राज्य सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम	21-25 मई, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
2.	लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम	11-15 जून, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
3.	कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यनीति प्रबंधन कार्यक्रम	16-20 जुलाई, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
4.	कोल इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यनीति प्रबंधन कार्यक्रम	11फरवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2019	एनसीजीजी, मसूरी

संलग्नक-VII

राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र के कार्यकलाप : जल और स्वच्छता

1. **राष्ट्रीय कार्यशाला**

क्र.सं.	कार्यशाला का नाम	अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1.	राष्ट्रीय कार्यशाला: भारत के लिए गैर-नेटवर्क स्वच्छता प्रणाली	27-28 फरवरी, 2019	होटल द सेवॉय, मसूरी

2. **क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षण स्थल
1.	जिला खूंटी, झारखंड के मुख्य एसबीएम (ग्रामीण) सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	16-18 अप्रैल, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
2.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	23-25 अप्रैल, 2018	एनएएससी परिसर, पूसा,नई दिल्ली
3.	भुवनेश्वर, ओडिशा में एसबीएम (ग्रामीण) पर द्वितीय स्तर के जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5-6 जून, 2018	एसआईआरडी एंड पीआर, भुवनेश्वर, ओडिशा
4.	राजस्थान राज्य के जल संसाधन इंजीनियरों के व्यक्तित्व विकास तथा प्रबंधन नीतिशास्त्र पर प्रशिक्षण– सह-कार्यशाला	6-9 जून, 2018	एनसीजीजी परिसर, मसूरी
5.	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एसबीएम (ग्रामीण) पर द्वितीय स्तर के जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	11-12 जून, 2018	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
6.	बिहार राज्य के लिए एसबीएम (ग्रामीण) पर द्वितीय स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	25-26 जून, 2018	बिपार्ड, पटना, बिहार
7.	जिला हजारीबाग, झारखंड के लिए एसबीएम (ग्रामीण) पर मीडिया प्रेस पत्रकारों और अधिकारियों के लिए तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम	20-22 जुलाई, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
8.	स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ स्थायीत्व पर जिला हजारीबाग, झारखंड के मुख्य एसबीएम (ग्रामीण) सदस्यों के लिए चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	24-26 सितम्बर, 2018	एनसीजीजी, मसूरी
9.	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एसबीएम (ग्रामीण) पर द्वितीय स्तर के जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-27 नवम्बर, 2018	जिला मुख्यालय, वाराणसी
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एसबीएम (ग्रामीण) पर द्वितीय स्तर के जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	29-30 नवम्बर,2018	जिला मुख्यालय, गोरखपुर